(d) The aims for which the Council has been established are of a long term nature and the Council has been endeavouring to achieve these objectives.

भारतीय रेलवे अधिनियम में संशोधन

*1684. **श्री मधु लिमये** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने संसद् की स्वीकृति लिए बिना ही भारतीय रेलवे अधिनियम में संशोधन किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने वर्ष 1666-67 के अपने वार्षिक प्रतिवेदन में, जिसे संसद् में पेश नहीं किया गया है, इस बात का उल्लेख किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रतिवेदन को संसद् के समक्ष प्रस्तुत करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). संसद् के अनुमोदन के बिना विधिक ग्रन्थ के किसी अधिनियम में संशोधन नहीं किया जा सकता और यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य का आशय किस संशोधन से है। फिर भी, 1966-67 में रेलवे निरीक्षणालय (रेल संरक्षा आयोग) के संचालन से सम्बन्धित रिपोर्ट के प्रारूप में यह सुझाव दिया गया है कि दुर्घटनाओं की सूचना और उनकी जांच के बारे में नियम बनाने के लिए भारतीय रेल अधिनियम, 1890(1890 का 9) की धारा 84 के अन्तर्गत निहित शक्तियां उस मंत्रालय को दे दी जायें जिसके प्रशासी नियंत्रण में रेल संरक्षा आयोग काम करता है।

(ग) जैसी कि प्रथा है, रेल संरक्षा आयोग की रिपोर्ट जब अन्तिम रूप से तैयार हो जायेगी तो पर्यटक और सिविल विमानन मंत्रालय जिसके अधीन रेल संरक्षा आयोग काम करता है, उसे सदन में प्रस्तुत करेगा।

(घ) सवाल नहीं उठता।

M/s. Standard Drum and Barrel Co.

*1685. **SHRI S. M. BANERJEE** : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6038 on the 2nd April 1968 and state :

(a) whether the approval of the Industrial Advisory Licensing Committee was obtained before granting a licence to M/s. Standard Drum and Barrel Co. ;

(b) when licence was granted to M/s. Hind Galvanising and Engineering Co. for manufacturing bitumen drums ;

(c) whether it is a fact that M/s. Hind Galvanising created a fresh capacity for manufacturing bitumen drums which was recognised by Government while the industry was on the 'Rejection List' ;

(d) whether it is obligatory on the part of Government to give bitumen drum sheets to the Refineries/Oil Companies for their requirement of bitumen drums ; and

(e) the percentage of the capacity of each licensed unit being utilised for the last 7 years on single shift and or multiple shifts basis ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) Approval of the Licensing Committee was obtained before granting industrial licence dt. 20th July, 1959 to M/s. Standard Drum and Barrel Company.

(b) and (c). No industrial licence was granted to M/s. Hind Galvanizing Engineering Co., for the manufacture of Bitumen Drums. According to the Registration certificate already held by the party, their activities included the manufecture of all steel drums other than steel drums of 40/45 gallon capacity. The item was on the rejection list for creating fresh capacity and no fresh capacity was created with the firm. Only their existing assessed capacity for steel drums other than 40/45 gallon barrels was split up, at the request of the firm, as follows in November 1966.

Asphalt-cum-bitumen drums —200 tonnes per annum.
Small drums —1400 tonnes per annum.